

# GS प्वाइंडर 3

## भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन

## भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन

### भारत का संवैधानिक विकास

- \* भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई
  - भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 के अंतर्गत
- \* कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था
  - रेगुलेंटिंग एक्ट, 1773 में
- \* भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी
  - भारत सरकार अधिनियम, 1935 के द्वारा
- \* भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था — 1937 में
- \* सही सुमेलित है—
 

नियंत्रण परिषद की स्थापना	— पिट्स का भारतीय अधिनियम, 1784
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना	— नियामक अधिनियम, 1773
इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति	— चार्टर अधिनियम, 1813
गवर्नर-जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति	— चार्टर अधिनियम, 1833
- \* 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं
  - प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध-शासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तान्तरण
- \* भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्वि-सदनीय बनाई गई
  - 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा
- \* राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है—
  - भारत सरकार अधिनियम, 1935 से
- \* भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया
  - चार्टर एक्ट, 1833 के अधिनियम ने
- \* भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है — भारत सरकार अधिनियम, 1935 के द्वारा
- \* एक 'संघीय व्यवस्था' और 'केंद्र' में 'द्वैध शासन' भारत में लागू किया गया था—
  - 1935 के अधिनियम द्वारा
- \* अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था
  - भारत सरकार अधिनियम, 1935 में
- \* 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां दी गई थी
  - गवर्नर जनरल को
- \* भारत शासन अधिनियम, 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है
  - देश के लिए लिखित संविधान
- \* 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है
  - क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है
- \* बर्मा, भारत से अलग हुआ
  - गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 के फलस्वरूप

\* वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था

— कुल 8 प्रांतों में

\* एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था

— ड्रिप्स मिशन द्वारा

\* भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था

— जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था,

भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना

\* कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था

— 10 लाख व्यक्ति

\* कैबिनेट मिशन के सदस्य थे

— पेथिक लार्सेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर

\* भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था

— कैबिनेट मिशन योजना, 1946 के अंतर्गत

\* 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे—

— जवाहरलाल नेहरू

\* कथन (A): वेवेल योजना के अनुसार, कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी।

कारण (R): वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता।

— कथन सही है, पर कारण गलत है।

\* भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था

— स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में

\* संविधान सभा के बारे में सही कथन हैं—

1. इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी

2. अल्पसंख्यक समुदाय जैसे- ईसाई, एंग्लो-इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया।

3. इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर सम्पत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मतधिकार सीमित था।

4. वह बहुदलीय निकाय थी

\* भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को

— विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया

\* संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था

— प्रांतीय सभाओं द्वारा

\* संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी

— डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने

\* भारत की 'संविधान निर्मात्री सभा' या संविधान सभा के अध्यक्ष थे

— डॉ. राजेंद्र प्रसाद

\* भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी

— 9 दिसंबर, 1946 को

\* भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ

— 9 दिसंबर, 1946

\* भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था—

— 22 जनवरी, 1947 को

\* संविधान सभा में 'उद्देश्य प्रस्ताव' या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था

— पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा

\* भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित सही कथन हैं—

1. पं. नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का, जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था।

2. उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है।

3. संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है।

\* भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे

— 12

\* भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा

— 2 वर्ष 11 माह 18 दिन

\* सही सुमेलन इस प्रकार है—

संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष — एच.सी. मुखर्जी

प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र — के.एम. मुन्शी

कांग्रेसी सदस्य

राजस्थान की रियासतों का — वी.टी. कृष्णामाचारी

प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान-

सभा के सदस्य

संघ-संविधान समिति के अध्यक्ष — जवाहरलाल नेहरू

\* संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था

— सरदार पटेल

\* भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे

— डॉ. बी.आर. अम्बेडकर

\* संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे

— सरदार पटेल

\* डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य सदस्य थे

— 6

\* संविधान सभा ने डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया

— 29 अगस्त, 1947 को

\* भारतीय संविधान के निर्माण के समय सांविधानिक सलाहकार थे

— बी.एन. राव

\* भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था

— बी.एन. राव द्वारा



- \* भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया  
— 22 जुलाई, 1947 ई. को
- \* संविधान निर्मात्री परिषद की 'झंडा समिति' के अध्यक्ष थे  
— डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
- \* भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था  
— 26 नवंबर, 1949 को
- \* भारतीय संविधान लागू हुआ था  
— 26 जनवरी, 1950 को
- \* संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया, क्योंकि  
— कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था
- \* भारतीय संविधान को अपनाया गया था  
— संविधानिक सभा द्वारा
- \* भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था  
— 26 नवंबर, 1949 को
- \* बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था—  
— बंबई प्रेसीडेंसी से
- \* डॉ. भीम राव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु हुई  
— क्रमशः 1891 तथा 1956 में
- \* 'जन गण मन' को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया  
— 1950 में
- \* भारत शासन द्वारा राजकीय चिह्न (State Emblem) अंगीकृत (Adopt) किया गया था  
— 26 जनवरी, 1950 से
- \* सही कथन हैं—  
1. तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार-विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम, 1935 के पास्ति होने के रूप में हुई।  
2. भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित आल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया।
- \* कथन (A) : भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।  
कारण (R) : इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है।  
— (A) और (R) दोनों सत्य हैं, परंतु (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- \* संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी  
— मौलाना आज़ाद ने
- \* भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, सुझाव दिया था  
— महात्मा गांधी ने
- \* "अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है।" यह कथन है  
— आइवर जेनिंग्स का

- \* "संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था" कहा था  
— ऑस्टिन ने
  - \* भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्याएं थीं  
— 15
- ## संविधान पर विदेशी प्रभाव
- \* भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है  
— यू.एस.ए. के संविधान से
  - \* भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है  
— संविधान
  - \* भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) की संकल्पना ली गई है  
— संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से
  - \* भारत की संघात्मक व्यवस्था संबंधित है  
— कनाडा से
  - \* भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में  
— न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) की प्रणाली है
  - \* न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था  
— भारत और यू.एस.ए. में है
  - \* भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में जो लक्षण पाया जाता है, वह है  
— संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय
  - \* भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची देन है  
— ऑस्ट्रेलिया की
  - \* भारतीय संविधान में 'राज्य के नीति निर्देशक तत्वों' की संकल्पना आधारित है  
— आयरलैंड के संविधान पर
  - \* राज्य सभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए थे  
— आइरिश गणतंत्र से
  - \* सही सुमेलन इस प्रकार है—  
(संवैधानिक प्रावधान) (स्रोत)

मूल अधिकार	- सं. रा. अमेरिका
शासन की संसदीय प्रणाली	- ग्रेट ब्रिटेन (यू.के.)
आपात उपबंध	- जर्मनी का वीमर संविधान
राज्य नीति के निर्देशक तत्व	- आयरलैंड

  - \* सही सुमेलन इस प्रकार है :  
विधि का शासन - इंग्लैंड  
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया - जापान  
राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना - कनाडा  
विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची - ऑस्ट्रेलिया  
मंत्रिमंडलीय सरकार - ब्रिटिश संविधान  
केंद्र-राज्य संबंध - कनाडा का संविधान  
भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है - कनाडा



- \* भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है  
— रूस (पूर्व सोवियत संघ) के संविधान से
- \* कथन (A) : भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है।  
कारण (R) : मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है।  
— (A) तथा (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- \* भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा ग्रहण की गई है  
— संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से
- \* लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ — अमेरिका से

## संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची

- \* भारतीय संविधान में हैं — 400 से अधिक आर्टिकल्स (अनुच्छेद)
- \* भारतीय संविधान में आरंभ में अनुच्छेद थे — 395
- \* भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं — 12
- \* सही कथन है—  
— भारत के संविधान में नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूचियों को संविधान (संशोधन) अधिनियम द्वारा जोड़ा गया।
- \* भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है — बाइस भागों में
- \* नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के जिस भाग में हैं, वह है — भाग 2
- \* सही सुमेलित हैं—  

नागरिकता	संविधान का भाग II
मौलिक अधिकार	संविधान का भाग III
राज्य	संविधान का भाग VI
- \* सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है—  

सूची-I	सूची-II
नए राज्यों का गठन	भारतीय संविधान का अनु. 3
नागरिकता	भारतीय संविधान का भाग-2
मौलिक अधिकार	भारतीय संविधान का भाग-3
प्रशासनिक अधिकारण की स्थापना	भारतीय संविधान का अनु. 323-A
- \* हमारे संविधान का वह भाग जिसमें तीन सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है — भाग IX
- \* संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में उल्लेख है  
— भारतीय संविधान के भाग 11 और अध्याय 1 में
- \* भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से वह अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्योरा देती है — पहली
- \* भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है  
— राज्य सभा में स्थानों के आवंटन को

- \* यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो, तो संविधान की अनुसूचियों में से जिस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए, वह है — पहली अनुसूची
- \* सही सुमेलित हैं—  

(अनुसूची)	(विषय)
चतुर्थ	राज्य सभा में स्थानों का आवंटन
षष्ठ	जनजातीय क्षेत्र
अष्टम	भाषा
नवम	भूमि सुधार
- \* सही सुमेलित हैं—

- |                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| सूची-I         | सूची-II                         |
| सातवीं अनुसूची | विधायी शक्तियों का वितरण        |
| आठवीं अनुसूची  | भाषाएं                          |
| नवीं अनुसूची   | कुछ अधिनियमों का विधिमन्थन      |
| दसवीं अनुसूची  | दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता |
- \* राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को, सैद्धान्तिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है — 9वीं अनुसूची में
  - \* भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है — समवर्ती सूची में
  - \* समवर्ती सूची का विषय है — आपराधिक मामले
  - \* भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है — जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन
  - \* समवर्ती सूची में है — शिक्षा
  - \* शिक्षा, जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया — 42वें संशोधन द्वारा
  - \* सही सुमेलन इस प्रकार है—  

विषय	सूची
वन	समवर्ती सूची
डाकघर बचत बैंक	संघीय सूची
जन स्वास्थ्य	राज्य सूची
  - \* सही सुमेलन इस प्रकार है  

केंद्र सूची	जनगणना
राज्य सूची	पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था
समवर्ती सूची	जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन
अवशिष्ट विषय (केंद्र के अधीन)	अंतरिक्ष अनुसंधान
  - \* भारतीय संविधान के वे प्रावधान, जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं—  
1. राज्य की नीति के निदेशक तत्व, 2. ग्रामीण और शहरी, स्थानीय निकाय, 3. पंचम अनुसूची, 4. षष्ठ अनुसूची, 5. सप्तम अनुसूची

- \* भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल-बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान हैं — दसवीं अनुसूची में
- \* भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख है — बैंकिंग, बीमा और जनगणना का
- \* वह विषय जो भारतीय संविधान की 'संघ सूची' से संबंधित हैं — रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे
- \* भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में उल्लेख है — रेलवे पुलिस का
- \* 'पंचायती राज' विषय सम्मिलित है — राज्य सूची में
- \* वह विषय जो भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-III समवर्ती सूची में शामिल है — दंड प्रक्रिया
- \* 'विवाह', 'विवाह विच्छेद' और 'गोद लेना' संविधान की सातवीं सूची में सम्मिलित किए गए हैं — सूची III - समवर्ती सूची में
- \* सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लिखित है — सातवीं अनुसूची में
- \* भूमि सुधार.....के विषयों के अंतर्गत है। — राज्य सूची
- \* भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है — पांचवीं अनुसूची में
- \* भारतीय संविधान की छठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, वह हैं — मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम
- \* भारत के संविधान में पांचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची के उपबंध किए गए हैं — अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए
- \* पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है — अनुच्छेद 243 के अंतर्गत
- \* संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची संबंधित है — पंचायती राज से
- \* "राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है, विधायिका में नहीं रखा जा सकता" — यह प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत आता है — अनुच्छेद 117 में
- \* वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है — अनुच्छेद 117 में
- \* भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है — अनुच्छेद-312 में
- \* सही सुमेलित हैं—  
भारत का निर्वाचन आयोग — अनुच्छेद 324  
अनुच्छेद 39A - समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता  
अनुच्छेद 40 - ग्राम पंचायतों का संगठन  
अनुच्छेद 44 - समान नागरिक संहिता

- \* सही सुमेलित है—

सूची-I (संविधान के अनुच्छेद)	
अनु. 124	-
अनु. 5	-
अनु. 352	-
अनु. 245	-

सूची-II (विषय)	
संघीय न्यायपालिका	
नागरिकता	
आकस्मिक प्रावधान	
विधायी शक्तियों का वितरण	

- \* सही सुमेलित है—

सूची-I अनुच्छेद	
14	-
36	-
74	-
368	-

सूची-II अनुच्छेद	
समानता का अधिकार	
नीति निर्देशक तत्व	
मंत्रिपरिषद	
संशोधन प्रक्रिया	

- \* सही सुमेलन इस प्रकार है—

सूची-I विधानतः नए राज्य को शामिल करना		सूची-II अनुच्छेद
समता का अधिकार	-	2
गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण	-	14
राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार	-	22
	-	111

- \* सही सुमेलित है—

सूची-I (संविधान का अनुच्छेद)	
अनुच्छेद 54	
अनुच्छेद 75	
अनुच्छेद 155	
अनुच्छेद 164	

सूची-II (अंतर्बस्तु)	
भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन	
प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति	
राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति	
राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति	

- \* सही सुमेलित है—

सूची-I अनुच्छेद	
323-A	
324	
330	

सूची-II अनुच्छेद	
प्रशासनिक अधिकरण	
निर्वाचन	
लोक सभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण	
लोक सेवा आयोगों के कार्य	
अनुच्छेद-280	
अनुच्छेद-360	



\* सुमेलिता है-

सूची-I

(संस्थान)

भारत का नियंत्रक एवं

महालेखा परीक्षक

संघ लोक सेवा आयोग

आपात स्थिति की घोषणा

सूची-II

(अनुच्छेद)

अनुच्छेद 148

अनुच्छेद 315

अनुच्छेद : 352

\* सही सुमेलन इस प्रकार है-

अनु. 215—उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना

अनु. 222—किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण

अनु. 226—विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति

अनु. 227—सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति

\* सही सुमेलित हैं-

सूची-I

अनुच्छेद 76

अनुच्छेद 131

कार्य करने का अधिकार

कार्य करने के लिए सही

और मानवीय स्थितियां

बच्चों के लिए मुफ्त तथा

अनिवार्य शिक्षा

सूची-II

भारत का महान्यायाधीश

सर्वोच्च न्यायालय का

क्षेत्राधिकार

अनुच्छेद 41

अनुच्छेद 42

अनुच्छेद 45

\* सही सुमेलन इस प्रकार है-

भारतीय संविधान का भाग IX - पंचायत

भारतीय संविधान का भाग VIII - संघ राज्य क्षेत्र

भारतीय संविधान का भाग IVA - मूल कर्तव्य

भारतीय संविधान का भाग IXA - नगर पालिका

\* सही सुमेलित हैं-

पंचायत - भाग 9

नगरपालिकाएं - भाग 9-क

सहकारी समितियां - भाग 9-ख

\* सही सुमेलन इस प्रकार है-

संविधान का भाग XV निर्वाचन

संविधान का भाग XVI कुछ वर्गों के संबंध में

विशेष उपबंध

संविधान का भाग XVII राजभाषा

संविधान का भाग XVIII आपात उपबंध

## उद्देशिका

\* निम्नलिखित अवतरण में,

“हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को,

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में,

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में

आज.....'X'.....को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।”

— 26 नवंबर, 1949

\* भारतीय गणतंत्र की 26-1-1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति, जब संविधान लागू किया गया था

— संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य

\* संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है—

— भारत तथा इंडिया नाम से

\* भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में शब्दों का सही क्रम है

— सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक

\* 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द हैं

— समाजवाद, पंथनिरपेक्षता

\* भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है— संविधान की प्रस्तावना

\* वह शब्द जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था — अखंडता

\* भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है —

एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र

\* संविधान की उद्देशिका के संबंध में सही है—

1. पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत “ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव” अंततोगत्वा उद्देशिका बना।

2. इसकी प्रकृति न्याययोग्य (Justiciable) नहीं है।

3. संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द (Override) नहीं कर सकता।

\* भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था

— ब्यातीसवें संशोधन द्वारा

- \* वह शब्द जो 26 नवंबर, 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे—

— समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता

- \* भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है—

— सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा

- \* 'भारत एक गणतंत्र है' इसका अर्थ है — भारत में वंशानुगत शासन नहीं है

- \* भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है — हम भारत के लोग शब्दों से

- \* 'हम, भारत के लोग (We the People of India)' शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया — संविधान की प्रस्तावना में

- \* "सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं"। यह सिद्धांत जाना जाता है — सार्वभौमिकता

- \* भारत के संदर्भ में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द का सही भाव व्यक्त करता है — भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है।

- \* भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है — लोक कल्याण

- \* भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है — आर्थिक स्वतंत्रता का

- \* भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है — धार्मिक न्याय

- \* संविधान की प्रस्तावना के बारे में कथन सही है — "समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष" शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे

- \* संविधान का वह भाग जो उसकी आत्मा कहलाता है — उद्देशिका

- \* भारतीय संविधान की प्रस्तावना को "हमारे संघ, प्रजातंत्रिक गणतंत्र की जन्मकुंडली" कहा — के.एम. मुंशी ने

- \* संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है — बी.आर. अम्बेडकर ने

- \* उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि 'उद्देशिका संविधान का भाग है' — बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में

- \* सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया — केशवानंद भारती विवाद में

- \* भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में 'आर्थिक न्याय' का उपबंध किया गया है

— उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्व में

- \* भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या की गई है

— मूल अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में

- \* भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है

— संविधान की प्रस्तावना

- \* भारत के संविधान की उद्देशिका में व्यवस्था की गई है

— तीन प्रकार के न्याय की

## शासन प्रणाली

- \* राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है — संप्रभुता

- \* भारतीय संविधान में जिस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, वह है — संसदात्मक

- \* भारतीय संविधान की विशेषता है

— संसदात्मक सरकार, संघात्मक सरकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका

- \* भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्योंकि — मंत्रिपरिषद्, लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है

- \* भारत के संदर्भ में, संसदीय शासनप्रणाली में निम्न सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं :

1. मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं।

2. जब तक मंत्रियों को संसद (लोकसभा) का विश्वास प्राप्त रहता है, तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं।

- \* संसदात्मक शासन व्यवस्था में — विधायिका का कार्यपालिका पर निबंधन होता है।

- \* राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं — राष्ट्रपति में

- \* भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं—

1. यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है।

2. इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है।

3. सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है।

- \* सही कथन हैं—

1. भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है।

2. भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है।

3. भारत में लोकतांत्रिक समाज है।

4. भारत एक कल्याणकारी राज्य है।

- \* भारतीय राजतंत्र की विशेषता है—

— एक संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन

- \* 'कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) का उद्देश्य है

— अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना

- \* भारतीय संविधान का दर्शन है

— कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता

- \* भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है — जनता

- \* अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है

— एकल कार्यपालिका



- \* भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि  
— जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है
- \* भारत का संविधान परिसंघीय विनिर्धारित होता है  
— केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण से
- \* भारतीय संविधान है — अंशतः कठोर और अंशतः लचीला
- \* भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर है — वार्षिक समीक्षा का
- \* कथन (A) : भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है।  
कारण (R) : उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है।  
— दोनों (A) और (R) सही हैं तथा (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- \* भारत के संविधान का संघीय लक्षण है  
— केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका
- \* भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व हैं  
— राज्यपालों की नियुक्ति, राज्य सभा में असमान प्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय सेवाएं
- \* भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित सही कथन है  
— संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है तथा एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है।
- \* कथन (A) : भारत का राष्ट्रपति परेक्षितः निर्वाचित होता है।  
कारण (R) : भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है।  
— दोनों (A) और (R) सत्य हैं तथा (R), (A) का एक मान्य स्पष्टीकरण है।
- \* कथन (A) : राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन-रक्त हैं।  
कारण (R) : लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं।  
— (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R) सही स्पष्टीकरण है (A) का।
- \* कथन (A) : भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है।  
कारण (R) : भारत एक संघीय राज्य नहीं है।  
— A सही है, परंतु R गलत है।
- \* कथन (A) : भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहु-आयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था।  
कारण (R) : विविधताओं के समंजन से एक सशक्त, न कि कमजोर, भारतीय राष्ट्रियता का निर्माण हुआ है।  
— (A) और (R) दोनों अपने आप में सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

- \* कथन (A) : महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं।  
कारण (R) : भारत में लोकतंत्र अधिक आत्म-सम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। — दोनों (A) और (R) सत्य हैं तथा (R), (A) का एक मान्य स्पष्टीकरण है।
- \* भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण हैं  
— यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है।
- \* कारण (A) : भारतीय संविधान अर्द्ध संघात्मक है।  
कारण (R) : भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक।  
— (A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
- \* भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है — जी. आस्टिन ने
- \* "भारत अर्द्ध संघात्मक राज्य है", कहा था — के.सी. क्वीयर ने
- \* "भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है।" कथन है — के.सी. क्वीयर का
- \* "संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है", कथन है — बी. आर. अम्बेडकर का
- \* भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में सही है—  
— धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति
- \* गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित है  
— एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो
- \* संवैधानिक सरकार वह है — जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है।

## राष्ट्रीय प्रतीक

- \* भारत का राष्ट्रीय पशु है — बाघ
- \* भारत का राष्ट्रीय पुष्प है — कमल
- \* भारत का राष्ट्रीय पक्षी है — मोर
- \* 'भारतीय राष्ट्रीय ध्वज' में चक्र प्रतीक है — न्याय का
- \* भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों (तीली) की कुल संख्या है — 24
- \* संपूर्ण राष्ट्र गान का वादन (गावन) काल है — 52 सेकंड

## राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र

- \* भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है  
— संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत
- \* नए राज्य के गठन (carve out) की शक्ति निहित है — संसद में
- \* भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है — संसद को



- \* एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकायी शक्ति प्राप्त है — संसद को
- \* संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है — राज्यों का यूनियन (संघ)
- \* नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही है — संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता, जब तक इसे उस राज्य के विधान मंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है, जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है।
- \* भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है — संसद में साधारण बहुमत द्वारा।
- \* भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है — राष्ट्रपति द्वारा
- \* कथन (A) : भारत संघ नहीं है  
कारण (R) : किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है।  
— A गलत है, किंतु R सही है।
- \* नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध है—  
— किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर
- \* सही कथन हैं—  
1. संविधान में "यूनियन ऑफ स्टेट्स" शब्द प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है।  
2. एस.के. धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी।  
3. पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभि सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी, राज्यों के पुनर्गठन में भाषायी आधार के पक्ष में नहीं थी।
- \* यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है, तो संशोधन करना आवश्यक होगा — प्रथम अनुसूची को
- \* भारत में संघ शासित प्रदेश हैं — 7
- \* लोकसभा में केंद्रशासित प्रदेशों के लिए सीटें (स्थान) आरक्षित हैं — 20
- \* राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर, 1956 को बनाए — 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य।
- \* भारत में — 29 राज्य एवं 7 संघशासित प्रदेश हैं
- \* संघ राज्य क्षेत्र हैं — अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दमन और दीव तथा पुडुचेरी

- \* वह राज्य जिसकी राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया — आंध्र प्रदेश (नई राजधानी के रूप में हैदराबाद के स्थान पर अमरावती प्रस्तावित)
- \* दिल्ली है — एक केंद्रशासित प्रदेश
- \* दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया — 69वें संविधान संशोधन द्वारा
- \* सही कथन हैं—  
(i) गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ  
(ii) दीव, खम्भात की खाड़ी (Gulf of Khambhat) में एक टापू है  
(iii) दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया
- \* सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया — 36वें संविधान संशोधन द्वारा
- \* राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम है — नगालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश
- \* भारतीय राज्यों का, उनके निर्माण के अनुसार, कालानुक्रम है — 1. सिक्किम, 2. अरुणाचल प्रदेश, 3. छत्तीसगढ़, 4. झारखंड
- \* छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया — 1 नवंबर, 2000 को
- \* उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई — वर्ष 2000 में
- \* विकल्प में दिए गए राज्यों का गठन निम्न वर्षों में हुआ था—  
राज्य गठन का वर्ष  
आंध्र प्रदेश - 1953  
हरियाणा - 1966  
हिमाचल प्रदेश - 1971  
सिक्किम - 1975
- \* सही सुमेसन है—  
राज्य स्थापना वर्ष  
नगालैंड - 1 दिसंबर, 1963  
मेघालय - 21 जनवरी, 1972  
सिक्किम - 16 मई, 1975  
अरुणाचल प्रदेश - 20 फरवरी, 1987
- \* राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम इस प्रकार है—  
राज्य निर्माण का वर्ष  
हरियाणा - 1966  
महाराष्ट्र - 1960  
राजस्थान - 1956
- \* सत्य कथन हैं—  
— गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया।  
बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया।  
हिमाचल प्रदेश पहले संघशासित प्रदेश की सूची में था।



- \* 'उल्फा' उग्रवादी संबंधित है — असम से
- \* 'पीपुल्स वार ग्रुप' नामक आतंकवादी संगठन स्थित है — आंध्र प्रदेश में
- \* कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य हैं — कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल
- \* भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी — 29 दिसंबर, 1953 को
- \* भाषायी आधार पर भारत में सर्वप्रथम गठन हुआ है — आंध्र प्रदेश का
- \* आंध्र प्रदेश एक भाषायी राज्य के रूप में गठित किया गया — 1953 में

## नागरिकता

- \* भारतीय संविधान प्रदान करता है — एकल नागरिकता
- \* भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है—  
— जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भू-भाग के सम्मिलन द्वारा
- \* नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2015 के अंतर्गत वह भारतीय कार्डधारक जो प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह हैं  
— एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, एक व्यक्ति का शरणार्थी/परपेक्षी जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह/पितामही, मातामह/मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे।
- \* सही कथन है  
— नगालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371A से लेकर 371I तक अंतर्विष्ट किए गए।
- \* दोहरी नागरिकता (Policy of Dual Citizenship) का सिद्धांत स्वीकार किया गया है — संयुक्त राज्य अमेरिका में
- \* नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है — संसद

## मूल अधिकार

- \* सही कथन है  
— भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट (1928) ने समर्थन दिया था।
- \* संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है — सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को

- \* 'मौलिक अधिकार' हैं — वाद योग्य
- \* मौलिक अधिकार — आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं
- \* भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं — अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत
- \* भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है — अनुच्छेद 14
- \* 'समानता का अधिकार' संविधान के निम्न अनुच्छेदों में के अंतर्गत दिया हुआ है— अनु. 14, अनु. 15, अनु. 16, अनु. 17 एवं अनु. 18
- \* शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर-सरकारी व गैर-अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है— अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत
- \* कथन (A) : सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है।  
कारण (R) : समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी।  
— (A) और (R) दोनों सही हैं और (A) का सही स्पष्टीकरण (R) है।
- \* संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद/राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों/कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है — अनुच्छेद 13
- \* भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है — मौलिक अधिकार के संदर्भ में
- \* भारतीय संविधान में 'स्वतंत्रता का अधिकार' चार अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो हैं — अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक
- \* भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया  
(a) संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त 'समाजवादी' शब्द  
(b) (a) को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना  
(c) (a) को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना
- \* धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (भारत के संविधान का अनुच्छेद 15) एक मूल अधिकार है, जिसे वर्गीकृत किया जाएगा — समता का अधिकार के अधीन
- \* भारतीय संविधान में, समता का अधिकार पांच अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये हैं — अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18
- \* भारतीय संविधान में जैसा निहित है, समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित है — कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता



\* मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है

— अनुच्छेद 24

\* आई.सी.सी.पी.आर. के अनुच्छेद \_\_\_\_\_ द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। — 24

\* अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है — अनुच्छेद - 17 द्वारा

\* न्यायालय उपस्थापित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य 'अस्पृश्यता' के आधार पर किया गया था, यदि ऐसा अपराध \_\_\_\_\_ के संबंध में किया गया है।

— अनुसूचित जाति के सदस्य

\* भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न उपायों द्वारा किया जा सकता है — 1. कानून बनाकर, 2. शिक्षा की उन्नति द्वारा, 3. जनजागरण के द्वारा

\* 'मद्रास राज्य बनाम दोरायराजन' 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप जिस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया, वह है — भेदभाव के विरुद्ध अधिकार

\* अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को मौलिक, सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया

— अनुच्छेद 17 के अंतर्गत

\* भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है — अनुच्छेद 19(1) अ में

\* भारतीय संविधान में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है — अनुच्छेद 19 में

\* स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में "बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से झुकना होने की स्वतंत्रता" के अंतर्गत नहीं आता है

— घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते

\* नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है — अवांछनीय आलोचना के कारण

\* व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है

— अनुच्छेद 21

\* अनुच्छेद 19(1) d को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है — एकांतता का अधिकार

\* धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं—

(I) धर्म प्रचार करने का अधिकार

(II) सिक्खों को 'कृपाण' धारण करने एवं रखने का अधिकार

(III) राज्यों को समाज-सुधारक विधि निर्माण का अधिकार

\* संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार, धर्म-स्वातंत्र्य का अधिकार अधीन है — सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा सदाचार के

\* सिक्खों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है — अनुच्छेद 25 के अंतर्गत

\* अनुच्छेद 25 का संबंध है — धर्म की स्वतंत्रता से

\* सही सुमेलित है—

अ

ब

अनुच्छेद 23 - मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्त श्रम का प्रतिबंध

अनुच्छेद 24 - कारखानों आदि में बातकों के नियोजन का प्रतिषेध

अनुच्छेद 26 - धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता

\* सही सुमेलित है—

मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्तश्रम का प्रतिषेध - अनुच्छेद 23

अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण - अनुच्छेद 29

संवैधानिक उपचारों का अधिकार - अनुच्छेद 32

\* अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है

— अनुच्छेद 30

\* भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं — मौलिक अधिकार

\* सही सुमेलन इस प्रकार है—

सूची-I

(भारतीय संविधान

का अनुच्छेद)

A. अनुच्छेद 16(2)

B. अनुच्छेद 29(2)

C. अनुच्छेद 30(1)

D. अनुच्छेद 31(1)

सूची-II

(प्रावधान)

- किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता।

- किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।

- सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा।

- किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाए उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।

\* मौलिक अधिकारों का संरक्षक है

— न्यायपालिका



\* सही कथन हैं—

(i) के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे

(ii) संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया।

(ii) बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई।

\* नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है — उच्चतम न्यायालय को

\* डॉ. बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है

— संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32)

\* कथन (A): संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉ. अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था।

कारण (R): अनुच्छेद 32, मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है।

— (A) तथा (R) दोनों ही सही हैं और (A) का सही स्पष्टीकरण (R) है।

\* व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकता है

— हैबियस कॉर्पस (बंदी-प्रत्यक्षीकरण) को

\* सही सुमेलन इस प्रकार है—

मौलिक कर्तव्य - संविधान का 42वां संशोधन

संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है - केशवानंद भारती केस  
इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध - संविधान का अनुच्छेद 23

\* सही सुमेलन इस प्रकार है—

सूची-I

सूची-II

उपाधियों का निषेध — अनुच्छेद 18

धार्मिक मामलों के प्रबंध — अनुच्छेद 26

की स्वतंत्रता

अल्पसंख्यकों की भाषा — अनुच्छेद 29

का संरक्षण

शिक्षा का अधिकार — अनुच्छेद 21A

\* संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया

— केशवानंद भारती बाद ने

\* भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत (बुनियादी ढांचा सिद्धांत) का प्रतिपादन किया है

— केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमे में

\* संपत्ति का अधिकार है — कानूनी अधिकार

\* संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया

— संविधान (चौवालीसवां संशोधन) अधिनियम 1978 द्वारा

\* वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक — वैधानिक/विधिक/कानूनी अधिकार

\* भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता है

— समान आवास का अधिकार

\* भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जिन 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, वे हैं — अनुच्छेद 14-18

\* भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है

— सूचना का अधिकार

\* सभी व्यक्तियों को प्राप्त है — विधि के समान संरक्षण का अधिकार

\* भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता

— व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का

\* सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है

— (1) आवास के अधिकार तथा (2) विदेश यात्रा के अधिकार को

\* किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि

1. इससे वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार का उल्लंघन होगा

2. इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा

3. राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है

\* विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है

— अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार

\* भारत में केवल नागरिकों को उपलब्ध हैं

(i) भेदभाव के विरुद्ध अधिकार

(ii) देशभर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता

(iii) चुनाव लड़ने का अधिकार

\* भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वह अधिकार, जो गैर-नागरिकों को भी उपलब्ध है — संवैधानिक निराकरण का अधिकार

\* भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त 'समाजवाद' शब्द को जिन अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई, वे हैं — अनुच्छेद 14 तथा 16

\* लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है— अनुच्छेद 16(1) और 16(2)

\* भारतीय संविधान मान्यता देता है

— धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को

\* छः वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों (शिशुओं) को शिक्षा का अधिकार — मूल अधिकार है

\* भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ गया

— 1 अप्रैल, 2010 को



- \* कथन (A) : राज्य छह से चौदह वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।

कारण (R) : एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है।

— (A) और (R) दोनों सही हैं और (A) का सही स्पष्टीकरण (R) है।

- \* वह अधिकार जो, राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है— व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार
- \* भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त 'हिंदू' शब्द सम्मिलित नहीं करता — भारतीयों को
- \* भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय/समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है, तो वह निम्न विशेष लाभ/लाभों का हकदार हो जाता है

— यह संप्रदाय/समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है।

यह संप्रदाय/समुदाय प्रधानमंत्री के 15 प्वाइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है।

- \* किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, यह प्रावधान है — अनुच्छेद 20 (3) में
- \* दोषसिद्धि के संबंध में अभियुक्त को दोहरे दंड एवं स्व-अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है

— अनुच्छेद 20

- \* विधि की सम्यक् प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है — अनुच्छेद 21 में

- \* बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रदत्त है — अनु.22 से

- \* प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है — 3 माह के लिए

- \* वह प्रलेख जिसे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है — बंदी प्रत्यक्षीकरण

- \* बंधुआ मजदूर (उन्मूलन) अधिनियम संसद ने पारित किया था — 1976 में

- \* जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है—  
(a) भारत के संविधान द्वारा  
(b) 10 दिसंबर, 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा  
(c) संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा

- \* पूर्ति कीजिए :  
'\_\_\_\_\_ बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है, जैसे मनुष्य बिना परछाई के।' — अधिकार

## राज्य की नीति के निदेशक तत्व

- \* राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है—

— सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना

- \* राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य है—  
— एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना,  
सामाजिक-आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना,  
एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना

- \* राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बारे में सही कथन हैं—  
1. ये तत्व देश के सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं।  
2. इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (एनफोर्सिबल) नहीं हैं।

- \* कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है—  
— राज्य के नीति-निदेशक तत्वों में

- \* भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति-निदेशक तत्वों की प्रेरणा हमें प्राप्त हुई — आयरलैंड संविधान से

- \* नीति-निदेशक सिद्धांत — बाद योग्य नहीं है

- \* भारत के संविधान के अनुसार, देश के शासन के लिए आधारभूत है — राज्य की नीति के निदेशक तत्व

- \* समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक — राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांतों का अंग है

- \* भारत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है — राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत

- \* राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है — अनुच्छेद 40

- \* भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन—  
— निदेशक सिद्धांत है।

- \* सही सुमेलन इस प्रकार है—

अनुच्छेद 40 : ग्राम पंचायतों का गठन

अनुच्छेद 41 : कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार

अनुच्छेद 44 : नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता

अनुच्छेद 48 : कृषि एवं पशुपालन का गठन

- \* कथन (A) : मनरेगा दर अर्ध परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है।

कारण (R) : रोजगार व अधिकार संविधान के भाग III में प्राविष्ट है।

— (A) सही है, परंतु (R) गलत है।



- \* राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांतों का सही सुमेलन इस प्रकार है—  
अनुच्छेद 51 : अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है।  
अनुच्छेद 41 : काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार  
अनुच्छेद 43 (क) : उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों के भाग लेने का अधिकार  
अनुच्छेद 48 (क) : पर्यावरण संरक्षण
- \* भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है — राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में
- \* भारत की विदेश नीति से संबंधित है — अनुच्छेद 51
- \* संविधान जिनके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, बच्चे, स्त्रियां तथा जनजातियां
- \* राज्य के नीति-निदेशक तत्व हैं—  
(a) मद्यनिषेध, (b) गौ-संरक्षण, (c) पर्यावरण-संरक्षण
- \* राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है — क्योंकि निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय हैं
- \* गांधीवादी सिद्धांत जो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं — ग्राम पंचायतों को संघटित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना
- \* राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांतों में से वह जिसके बारे में संविधान शांत है — प्रौढ़ शिक्षा
- \* राज्य का नीति-निदेशक सिद्धांत जो संविधान में बाद में जोड़ा गया — मुफ्त कानूनी सलाह
- \* राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है — सूचना का अधिकार
- \* नीति-निदेशक तत्व है — समान नागरिक संहिता
- \* राज्य के नीति-निदेशक तत्वों में है—  
— राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं की समान कार्य हेतु समान वेतन, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, — काम हेतु न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं में रहें
- \* 'राज्य के नीति-निदेशक सिद्धान्त एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है।' कहा था — के.टी. शाह ने

## मूल कर्तव्य

- \* भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को रखा गया है — तीसरे स्थान पर
- \* भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा 'मूल कर्तव्यों' को सम्मिलित किया गया है — अनुच्छेद 51A में

- \* भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया — स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर
- \* संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया — 1976 में
- \* भारत के संविधान का वह भाग जिसमें मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं — भाग IVA (4 क) में
- \* भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए — 42वें संविधान संशोधन द्वारा
- \* भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं — अनुच्छेद 51-क में
- \* मौलिक कर्तव्यों से संबंधित सही कथन है — उन्हें सैधनिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना सैधनिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है
- \* भारत में मौलिक कर्तव्य है — हमारी भिन्नी-जुती संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना
- \* एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है—  
— प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें
- \* भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित है — देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना।
- \* भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित हैं — मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा। वैज्ञानिक मनेदशा और खोज की भावना का विकास। वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न।
- \* भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है — वन्य प्राणी का संरक्षण
- \* "भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार।" शामिल है — अनुच्छेद 51-क में
- \* सही कथन है — मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। भारतीय संविधान के भाग-IV क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। अनुच्छेद 51-A प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है।
- \* भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं — ग्यारह
- \* भारतीय संविधान के भाग IVA (मूल कर्तव्य) में वर्णित है — राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना। भारत के सभी लोगों के मध्य भाई-चारे का भाव विकसित करना। हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान घरोहर की रक्षा करना।



\* सही सुमेरित है—

संविधान का भाग विषय

(a) भाग II नागरिकता

(b) भाग III मूल अधिकार

(c) भाग IV राज्य की नीति के निदेशक तत्व

\* "भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें।" यह उपबंध किया गया है — मूल कर्तव्य में

## राष्ट्रपति

\* कथन (A): संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है।

कारण (R): राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है।

— (A) सही है, किन्तु (R) गलत है।

\* भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है — अप्रत्यक्ष मतदान से

\* कथन (A): भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है।

कारण (R): एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है, जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है।

— (A) और (R) दोनों सही हैं और (A) का सही स्पष्टीकरण (R) है।

\* भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है

— एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा

\* राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं

— संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य,

सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य

\* राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है

— निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है।

\* भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम — पचास निर्वाचकों द्वारा

\* राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि

— वह राज्य विधान मंडल में उच्च सदन का सदस्य हो

\* भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या, उस राज्य की जनसंख्या को विधान सभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की एक हजार के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में "जनसंख्या" से तात्पर्य यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है

— 1971 की जनगणना द्वारा

\* राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक है

— आयु 35 वर्ष है, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो

\* एक सांसद अथवा विधान सभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु

— निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी।

\* राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है

— अनुच्छेद 57

\* अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है, तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है — भारत के सर्वोच्च न्यायालय को

\* राष्ट्रपति पांच वर्ष तक अपने पद पर रहता है—

— अपने पद ग्रहण के दिन से

\* भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है

— भारत के उपराष्ट्रपति को

\* भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है

— संसद द्वारा

\* राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है— अनुच्छेद 61 के द्वारा

\* राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है

— संसद के किसी भी सदन द्वारा

\* भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए आवश्यक है

— कम से कम 14 दिनों की पूर्व सूचना

\* भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचकगण का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है

— राज्यों की विधान सभाएं

\* भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है

— अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया

\* पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए

— रिक्ति होने की तिथि से छह माह के भीतर

\* जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है

— 6 माह तक

\* यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा

— सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश

\* भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष (Executive Head) है

— राष्ट्रपति

\* संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं

— अनुच्छेद 53 के अंतर्गत



- \* **कथन (A):** संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं
- \* **कारण (R):** कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं।
- (A) और (R) दोनों सत्य हैं, किंतु (R) सही स्पष्टीकरण नहीं है (A) का।
- \* सही कथन है
  - प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो।
- \* भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है — भारत का राष्ट्रपति
- \* राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है— 44 वें संशोधन द्वारा
- \* राष्ट्रपति लोक सभा को बंग कर सकते हैं
  - केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुमति पर
- \* अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोक सभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है— — राष्ट्रपति द्वारा
- \* भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कथन सही है—
  - वह संसद का एक संघटक भाग है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है।
- \* भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया, वह था—
  - भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक
- \* एक राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था, जिसे संविधानिक शब्दावली में 'जेबी निषेधाधिकार' कहा जाता है, वह थे
  - ज्ञानी जैल सिंह
- \* राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं — अनुच्छेद 111 के अंतर्गत
- \* जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है
  - राष्ट्रपति को
- \* राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है
  - विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोककर रखना तथा संसद को संदेश भेजना
- \* राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है
  - विधेयकों पर स्वीकृति देना
- \* जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने (वर्ष 2002 में) चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने उसे अपनी सहमति दी — अनुच्छेद 123 के अंतर्गत
- \* भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है
  - अनुच्छेद 123 के अंतर्गत
- \* राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद रखा जाना आवश्यक है — 6 सप्ताह तक
- \* भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है
  - वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री
- \* राष्ट्रपति नियुक्ति करता है—
  - भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल
- \* भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है—
  - प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त
- \* संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है — अनुच्छेद 160 में
- \* भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है
  - राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का
- \* राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है — अनुच्छेद 143
- \* भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही नहीं है — राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए
- \* संविधान के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति की 'शक्ति' नहीं है
  - संसद के सदनों को संदेश भेजना
- \* भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है, कि वह
  - सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए
- \* राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक — न्यायिक शक्ति है
- \* भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त प्राधिकार हैं
  - औपचारिक (स्टिट्यूलर) और विधिक, संवैधानिक और नाममात्र
- \* भारतीय संविधान के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे संसद के पटल पर रखवाएं
  - संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को
- \* वह संवैधानिक विशेषाधिकार, जो राष्ट्रपति का नहीं है
  - वितीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना
- \* संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है
  - केंद्रीय मंत्रिमंडल
- \* **कथन (A):** भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से निम्न है।
- \* **कारण (R):** भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। — A सही है, परंतु R गलत है।



- \* कथन (A) : राष्ट्रपति संसद का भाग है।  
कारण (R) : संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है।
- (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।
- \* कथन (A) : रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है।  
कारण (R) : प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं।

— (A) सही है, परंतु (R) गलत है।

- \* स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे — बिहार से
- \* भारत के चौथे राष्ट्रपति — श्री बी.वी. गिरि थे
- \* दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति थे — डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- \* भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है — नीलम संजीव रेड्डी
- \* सूची-I का सूची-II से सुमेलन निम्नवत है-

सूची-I (राष्ट्रपति)	सूची-II (अवधि)
फखरुद्दीन अली अहमद	1974-1977
एन. संजीव रेड्डी	1977-1982
डॉ. ज़ाकिर हुसैन	1967-1969
बी.वी. गिरि	1969-1974

- \* राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे — नीलम संजीव रेड्डी
- \* भारत के राष्ट्रपतियों में 'दार्शनिक-राजा' अथवा 'दार्शनिक-शासक' के रूप में जाना जाता है — डॉ. राधाकृष्णन
- \* भारत के राष्ट्रपतिबों में से ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है — बी.वी. गिरि
- \* भारत के राष्ट्रपति को 'मिसाइल मैन' की संज्ञा दी जाती है — डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को
- \* भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, वह — जस्टिस एम. हिदायतुल्ला
- \* कथन सत्य है-  
— राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम-से-कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति राज्य सभा का सभापति बनता है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे
- \* कथन : अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।  
कारण : राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है।  
— कथन सही है, परंतु कारण गलत है।
- \* श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम था — 12वां
- \* एक विधेयक, जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है और बाद में अधिनियम बन जाता है — जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है

- \* किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है — राष्ट्रपति को
- \* "वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है" यह उक्ति लागू होती है — राष्ट्रपति
- \* भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में बिहार का राज्यपाल रह चुका था — डॉ. ज़ाकिर हुसैन (वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी)
- \* राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था —

— एडविन ल्यूटियनस द्वारा

## उपराष्ट्रपति

- \* भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचकगण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं — संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य
- \* कथन (A) : कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा, जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है।  
कारण (R) : उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपर्युक्त वक्तव्यों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर सही है — दोनों (A) और (R) सत्य हैं तथा (R), (A) का एक सत्य स्पष्टीकरण है।
- \* उपराष्ट्रपति से संबंधित सही कथन हैं — किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, उप-राष्ट्रपति का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का।
- \* भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है — लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से
- \* भारत का उपराष्ट्रपति
  1. भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है।
  2. के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य (दायित्व) नहीं है।
  3. राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है।
  4. राष्ट्रपति की पद-त्याग, अक्षमताकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।
- \* उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है — राज्य परिषद (राज्य सभा) के प्रस्ताव के द्वारा
- \* उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है — राज्यसभा में
- \* राज्यसभा का सभापति है — उपराष्ट्रपति
- \* एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है, जो उसका सदस्य नहीं होता है — राज्यसभा
- \* दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे — डॉ. एस. राधाकृष्णन और बी.वी. गिरि
- \* मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक — 12वां



## केंद्रीय मंत्रिपरिषद्

- \* भारत के प्रधानमंत्री के विषय में सही है  
— प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद् का वास्तविक नेता है।
- \* भारत का प्रधानमंत्री \_\_\_\_\_ होता है। — नियुक्त
- \* सत्य कथन है—  
(a) राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है।  
(b) कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता।  
(c) एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए दो मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी।
- \* भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है— — केंद्रीय सरकार का
- \* भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का—  
— प्रधानमंत्री के
- \* कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं — केवल कैबिनेट मंत्री
- \* संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है  
— प्रधानमंत्री के पास
- \* सही कथन है  
— राष्ट्रपति, भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा।
- \* यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, तो  
— वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे
- \* भारतीय संविधान का प्रावधान मंत्रिपरिषद् की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है  
— अनुच्छेद 75
- \* आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है — लोक सभा का सदस्य
- \* "कौन्सिल ऑफ साइंटिफिक एवं इंडस्ट्रियल रिसर्च" का अध्यक्ष है  
— भारत का प्रधानमंत्री
- \* राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है — प्रधानमंत्री
- \* भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय  
— जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे छः माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए।
- \* भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए  
— 25 वर्ष
- \* उपप्रधानमंत्री पद का सृजन  
— संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ।
- \* प्रधानमंत्री को — राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है
- \* भारत का प्रधानमंत्री—  
— अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है
- \* जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय मंत्री रह सकता है—  
— छह माह तक
- \* भारत की संसद के संबंध में कथन सही है  
— संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, संसद का सर्वप्रमुख कार्य है, मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए
- \* मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है  
1. लोकसभा के प्रति  
2. एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत  
3. अनुच्छेद 75(3) के अनुसार
- \* केंद्रीय मंत्रिपरिषद् के त्यागपत्र देने के उपरांत सही स्थिति है  
— राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक, उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए। अपरस्थ मंत्रिपरिषद् अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी।
- \* सही कथन हैं  
संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे। विधि-निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को सूचित करेंगे।
- \* भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है  
— प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे, तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए
- \* भारत में मंत्रिपरिषद् रख सकती है — विश्वास प्रस्ताव
- \* बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद् को त्यागपत्र देना पड़ेगा — लोकसभा के सदस्यों द्वारा
- \* अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है — स्पीकर की
- \* लोकसभा में मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध 'अविश्वास' का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है — 50
- \* भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सही कथन है—  
1. भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है।  
2. अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुरःस्थापित किया जा सकता है।
- \* लाभ के पद का निर्णय (Decision) करेगा — संघीय संसद



- \* भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका.....के अधीन रहकर कार्य करती है। — विधायिका
- \* उत्तर प्रदेश का नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में खास मंत्री बना ? — कैलाश नाथ काटजू
- \* स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे — स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर.के.पणमुखम चेटी थे। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर, 1947 को प्रस्तुत किया था। 1949 में उनके स्थान पर जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था।
- \* भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री था — बी.आर. अम्बेडकर
- \* भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है — बजट शब्द
- \* भारत के 12 वें प्रधानमंत्री थे — देवेगौड़ा
- \* सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है—  
(i) विश्वनाथ प्रताप सिंह — 2 दिसंबर, 1989–10 नवंबर, 1990  
(ii) चंद्रशेखर - 10 नवंबर, 1990 – 21 जून, 1991  
(iii) एच.डी. देवेगौड़ा - 1 जून, 1996– 21 अप्रैल, 1997  
(iv) इंदर कुमार गुजराल—21 अप्रैल, 1997–18 मार्च, 1998  
(v) अटल बिहारी वाजपेयी— 19 मार्च, 1998–22 मई, 2004  
नोट- उल्लेखनीय है कि अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल इस प्रकार है— 16 मई, 1996 से 1 जून, 1996 तक,  
19 मार्च, 1998 से 26 अप्रैल, 1999 तक तथा 13 अक्टूबर, 1999 से 22 मई 2004 तक।
- \* एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं—  
— जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह
- \* भारत के प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई — ताल बहादुर शास्त्री की
- \* भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे — चंद्रशेखर
- \* भारत के प्रधानमंत्रियों में से अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ — चौधरी चरण सिंह
- \* संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह— — अनुच्छेद 352 में
- \* भारत के केंद्रीय मंत्री रहे हैं—  
1. वी. पी. सिंह 2. आर. वेंकटरमण  
3. वाई. बी. चव्हाण 4. प्रणब मुखर्जी
- \* उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई, प्रधानमंत्री — नरसिम्हा राव द्वारा

- \* मनमोहन सिंह के संबंध में सही कथन है—  
— भारत के पूर्व वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि
- \* कथन : (1) मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं।  
कारण : (2) संसदीय प्रणाली में 'मंत्रियों का उत्तरदायित्व' का सिद्धांत कार्य करता है।  
— कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- \* कथन (A) : भारत संघ में मंत्रिपरिषद् संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के प्रति उत्तरदायी है।  
कारण (R) : लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं।  
— कथन गलत है, पर कारण सही है।
- \* कथन (A) : किसी व्यक्ति को उपप्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है।  
कारण (R) : वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।  
— (A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- \* संविधान संशोधनों में से एक, बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या, प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी — 91वां
- \* केंद्रीय सरकार के संदर्भ में सही है  
— 15 अगस्त, 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी।
- \* अधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है — श्वेत पत्र
- \* प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा, जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़बट न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े — अनुच्छेद 257
- \* संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन आधारित था  
— गोपालस्वामी आयोग रिपोर्ट पर
- \* मंत्रिमंडल सचिवालय का/के कार्य हैं/हैं  
1. मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना  
2. मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता
- \* सही सुमेलन है—  
(a) जे. एल. नेहरू — शांति वन  
(b) एल. बी. शास्त्री — विजय घाट  
(c) इंदिरा गांधी — शक्ति स्थल
- \* 'जय जवान जय किसान' का नारा दिया — ताल बहादुर शास्त्री



## महान्यायवादी और सी. ए. जी.

- \* भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है  
— अटॉर्नी जनरल
- \* राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपना पद धारण करता है  
— भारत का महान्यायवादी
- \* भारत के महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है — राष्ट्रपति द्वारा
- \* भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है  
— महान्यायवादी
- \* अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्यक्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा  
— महान्यायवादी को
- \* भारत के महान्यायवादी (Attorney General) के विषय में सही है—  
(1) वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है  
(2) उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं
- \* संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है  
— भारत के अटॉर्नी जनरल को
- \* भारत का महान्यायवादी  
(1) लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है  
(2) लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है।  
(3) लोकसभा में बोल सकता है
- \* सॉलिसिटर जनरल होता है  
— कानूनी/न्यायिक सलाहकार
- \* कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है?  
— एडवोकेट जनरल (महाविक्ता)
- \* भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है—  
— राष्ट्रपति द्वारा
- \* भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है  
— अनुच्छेद 148 के अंतर्गत
- \* भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है  
— भारत के राष्ट्रपति को
- \* भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था  
— संविधान द्वारा
- \* भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है  
— 6 वर्ष
- \* भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सही है—  
(a) उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।  
(b) उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है।  
(c) सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं।
- \* भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन किया जाता है—  
(a) भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना  
(b) आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना  
(c) सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना
- \* लोक निधि के फलौत्पादक और आशयित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ-साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक (CAG) के कार्यालय का महत्त्व है—  
(i) CAG की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार-विमर्श करती है; (ii) CAG के प्रतिवेदनों से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं, जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया है।
- \* नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है—  
— संसद की
- \* संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है  
— भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक
- \* नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अपने पद से उसे हटाया जाता है  
— संसद के दोनों सदनों के संयोजन पर
- \* भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है  
— लोक लेखा समिति का
- \* 1971 का संशोधन (महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति) अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सी.ए.जी. को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया  
— 1976 में
- \* लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है  
— नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को
- \* लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रिया-कलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत आते हैं—  
(a) सार्वजनिक खर्च का परीक्षण  
(b) सार्वजनिक राजस्व  
(c) वित्तीय प्रशासन